Prakasam districts, 643 in Karim Nagar, 627 habitations are in Mahaboobnagar, and so on. A total number of 8,517 habitations are facing the problem of brackishness. Out of these 8,517,1802 habitations are in Srikakulam, 1,232 habitations are in Visakhapatnam and 1,002 habitations are in East Godavari district alone. Similarly, out of 637 stations in 23 districts, 203 stations are having excess nitrate in ground water. The contaminated water in those habitations is badly affecting the poor villagers with all sorts of diseases posing a continuous health hazard for them.

The Central Government is implementing the Rajiv Gandhi National Drinking Water Mission in the State, but it is laying more emphasis on providing water for habitations. The State Government has also prepared such plan, but the need of the hour is to set up enough water treatment plants, and where the problem is acute, provision for piped water should be made. It will require huge funds.

I, therefore, urge upon the Central Government to release adequate Central grants to Andhra Pradesh for improving the quality of water and for providing safe drinking water to the people on priority basis. Thank you.

SHRIMATI VANGA GEETHA (Andhra Pradesh): Sir, I associate myself with it.

Establishment of a Doordarshan Kendra at Khajuwala

श्रीमती जमना देवी बारूपाल (राजस्थान) : माननीय सभापति महोदय, मै आपके द्वारा केन्द्र सरकार से आग्रह करूगी कि बीकानेर जिले में 180 किलोमीटर दूर खाजूवाला तहसील में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना करने की अत्यंत आवश्यकता है क्योकि खाजूवाला पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है। यहां की जनसंख्या हजारों में है। यहां के सभी बाशिन्दे किसान, मजदूर और गरीब लोग हैं। इन किसानो को 54 वर्ष बाद भी अपने देश के कार्यक्रमों की या सीमा सुरक्षा की बातों की जानकारी नहीं मिल पाती है। ये लोग केवल पाकिस्तानी कार्यक्रम ही देख और सुन सकते हैं। जेटली साहब यहां बैठे हैं, मैने एक बार उनसे भी इस संबंध में आग्रह किया था। उन्होने कहा कि वे इसका सर्वे कराएंगे लेकिन दो वर्ष के बाद भी मुझे कोई संतोषजनक उत्तर नही मिला है। बहुत ही लाड़ली बेटी की तरह सुषमा जी भी हमारे सामने बैठी हूई हैं। मैने उनसे भी कई बार मौखिक तौर पर आग्रह किया है और आज सदन के माध्यम से भी आग्रह कर रही हूं कि जो ग्रामीण विकास की योजनाएं चलाई जाती है, उनका लाभ वहां के लोगो को नही मिल पाता है। खाजूवाला के किसानो को ऐसे कार्यक्रम देखने को या सुनने को नही मिल पातें हैं। 54 वर्षो के बाद भी ये लोग सरकार के उदासीन रवैये से काफी दुखी हैं। सरकार की उदासीनता पर खिन्नता प्रकट करते हुए ये लोग यह कहने से नही चूकते कि वोटों की आवश्यकता के बाद सरकार को गरीब किसानों से क्या लेना-देना है? मैं पुनः सरकार से आग्रह करती हूं की वह यहां के किसानों को, लोगो को पाकिस्तानी प्रोगाम्स देखने से बचाए और भारत में होने वाले विकास कार्यक्रमों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य मनोरंजन कार्यक्रमों की जानकारी

प्रदान करने हेतु खाजूवाला में शीघ्र दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना करने की कृपा करे। यह सीमावर्ती क्षेत्र है और यहां हजारों की संख्या में जवानों का आवागमन होता रहता है। जवानों को भी जब अपने देश के कार्यक्रमों को देखने और सुनने का लाभ नहीं मिलेगा तो मैं सोचती हूं कि यहा मुद्दा बहुत ही अफसोसजनक है। इसलिए सामने बैठी हुई मैडम, इस पर थोड़ा गौर करें और आश्वासन आपने दिए हैं, उन्हे पूरा करें।.....(**व्यवधान**).....

सूचना और प्रसारण मंत्री(**श्रीमती सुषमा स्वराज**) : पांच मिनट में बेटी मैडम हो गई?

श्रीमती जमना देवी बारूपाल : इसलिए आप जल्दी से जल्दी खाजूवाला में दूरदर्शन कैन्द्र की स्थापना कराने की मेहरबानी करें। आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद । मुझे आशा है कि आप चंद दिनो में ही इस काम को पूरा कराने में अपना योगदान देंगी ।

श्रीमती सुषमा स्वराज : हमने आपकी सुनी ही नहीं है बल्कि हम इसे मानेंगे भी ।

DISCUSSION ON THE WORKING OF THE MINISTRY OF LABOUR

SHRI JIBON ROY (West Bengal): Sir, after a lapse of nine long years, we are discussing labour in this House. Probably, for the first time we are discussing labour since the policy of LPG - liberalisation, privatisation and globalisation - was introduced in our country. The ILO report of 1997-98 has reviewed the global effect of LPG. The report has mentioned that globalisation has widened the inequalities. It has further noted that globalisation has created more insecure position for the labour. I wish to know from the hon. Minister, who has emerged through the wave of social justice movement, what is his experience about the functioning of his own Ministry. It is said that in the year 1993-94, seven paise of every rupee of the GDP was being allotted for the labour. Now, in the Budget for 2001-02, the allotment is half-a-paise of every rupee of the GDP. From seven paise, it has gone down to half a paise. This reflects the attitude of this Government towards the labour and towards your Ministry. I wish to know the reaction of the hon. Minister on this point.

Sir, I would also like to know whether his Ministry was consulted before the policy of so-called labour reforms was announced outside the House and in this House. Secondly, if his Ministry was consulted, on how many occasions did he call the trade unions and discuss the different aspects of the so-called labour reforms with them. Thirdly, I would like to know whether he can give an assurance to the House that nothing would be done unless there is a total unanimity among the labour so far as labour reforms are concerned.